देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 12.02.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की; अपराधियों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई के दिए निदेश।
- शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा– उत्तराखंड सरकार विद्यालयी शिक्षा में त्रि–स्तरीय शैक्षणिक ढांचा लागू करेगी।
- प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दी।
- देहरादून के धौलास भूमि प्रकरण में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आवंटन शर्तों और अवैध प्लाटिंग की जांच शुरू।

कानून व्यवस्था समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों में तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और दोषियों पर कठोर व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आदतन और संगठित अपराध में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें।

मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरी सक्रियता और जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली मजबूत करने, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने तथा शहरी क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

घटनास्थल निरीक्षण

इस बीच, थाना डालनवाला क्षेत्र में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर उपलब्ध साक्ष्यों और अब तक की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की।

पुलिस महानिरीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को निर्देश दिए कि घटना में शामिल आरोपियों की शीघ्र पहचान कर विशेष टीमें गठित की जाएं और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी व सर्विलांस संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए।

शैक्षणिक ढांचा

उत्तराखंड सरकार विद्यालयी शिक्षा में शैक्षणिक संवर्ग के लिए त्रि–स्तरीय ढांचा बनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रस्ताव को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए।

बैठक में बताया गया कि डायट में रिक्त प्रवक्ता संवर्ग के 222 पदों को भरने के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, ताकि स्थायी नियुक्ति हो सके और प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक अपने मूल विभाग में लौट सकें।

डॉक्टर रावत ने निर्देश दिए कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। समय पर पुस्तकें उपलब्ध न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इसके साथ ही एससीईआरटी के ढांचे के गठन, नियमावली तैयार करने, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति और स्कूल–कॉलेजों की स्थापना में भूमि दान करने वाले परिवारों को भर्ती में प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

तैयारियां

आगामी कुंभ मेला–2027 की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार में आयोजित बैठक में मेला व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए गए।

मेलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कुंभ मेला क्षेत्र में चार जिलों के अंतर्गत लगभग डेढ़ सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र को 32 सेक्टरों में विभाजित कर माइक्रो प्लानिंग तैयार की गई है। इनमें हरिद्वार में 23, देहरादून में 4, टिहरी में 2 और पौड़ी गढ़वाल में 3 सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। सभी सेक्टरों में सड़क, पेयजल, विद्युत, जन–सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्थायी और अस्थायी कार्य चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। दो स्थायी पार्किंग स्थलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है। मेला क्षेत्र की आंतरिक सड़कों के सुधार और जलभराव की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार नगर में सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को एक सप्ताह के भीतर ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। मेलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त सुझावों को अंतिम कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा, ताकि कुंभ मेले का आयोजन सुव्यवस्थित और सफल ढंग से किया जा सके।

मंजूरी

प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दी है। शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार पांच सौ रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पूर्ण रूप से शय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। सात दिन जेल गए या घायल आंदोलनकारियों की पेंशन छह रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये प्रतिमाह तथा अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन चार हजार 500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

कार्रवाई

देहरादून के धौलास स्थित भूमि प्रकरण में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर ग्राम धौलास

में संबंधित भूमि का स्थलीय निरीक्षण और पैमाइश कराई है। प्रशासन के अनुसार शेखुल हिंद एजुकेशन चौरिटेबल ट्रस्ट को यह भूमि शैक्षणिक उद्देश्य से आवंटित की गई थी। अब यह जांच की जा रही है कि आवंटन की शर्तों का पालन किया गया या नहीं। तहसील प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि करीब 20 एकड़ कृषि भूमि पहले 15 व्यक्तियों को बेची गई और बाद में उसे छोटे–छोटे भूखंडों में कई अन्य लोगों को विक्रय किया गया। भूमि विक्रय की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उसका स्वरूप कृषि ही रहेगा और उसे अकृषि घोषित कर बिक्री नहीं की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पैमाइश की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद जमींदारी एक्ट के तहत विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे और लोगों से बिना अनुमति भूमि खरीदने से बचने की अपील की थी।

निरीक्षण

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून के बसंत विहार स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति, फाइल निस्तारण और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के बाद उन्होंने बागेश्वर और गरुड़ की जीआईएस आधारित महायोजना की समीक्षा की। बैठक में नगरीय विस्तार, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सचिव ने निर्देश दिए कि महायोजना को स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाए।

औचक निरीक्षण के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति की भी जांच की गई। बिना अनुमति अनुपस्थित कार्मिकों से स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्यालयीन अनुशासन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

खाद्य सुरक्षा

महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरिद्वार ज़िले में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में की गई।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने कांवड़ पटरी मार्ग चिड़ियापुर, चंडीघाट और हरकी पैड़ी क्षेत्र के स्थायी और अस्थायी खाद्य प्रतिष्ठानों तथा कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज का निरीक्षण किया। कुल 28 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें अनियमितता पाए जाने पर 7 खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया।

निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी तिथि वाली कोल्ड ड्रिंक की 118 बोतलें मौके पर नष्ट कराई गईं।

ऊंचापुल ज्वालापुर स्थित एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के निरीक्षण में खाद्य पदार्थ जमीन पर रखे मिले और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर स्टोरेज मालिक को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्सपायरी हो चुकी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।